भोपाल | शनिवार । 14 फरवरी 2026 । वर्ष 70 । अंक 23 । पृष्ठ 12 । मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

नागरिक देवो भव : -मोदी

1189 करोड़ की लागत आई निर्माण पर | **2.26** लाख वर्ग फुट में फैला है सेवा तीर्थ | **03** मुख्य इमारतें हैं परिसर में

नई दिल्ली, 13 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की नई इमारत 'सेवा तीर्थ' और कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन किया. सेवा तीर्थ में पीएम ऑफिस होगा जबकि कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 में कई प्रमुख मंत्रालय होंगे. बिल्डिंग की खास बात यह है कि इस पर नागरिक देवो भव: लिखा गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स 'सेवा तीर्थ' में महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े अहम फैसलों की फाइलों पर साइन किए. सरकार के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य इन वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाना है. प्रधानमंत्री ने पीएम राहत योजना से जुड़ी फाइलों पर भी साइन किए. इस पहल के तहत, एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे उनके इलाज में देरी न हो. साथ ही लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दोगुना कर 3 करोड़ से छह करोड़ करने का निर्णय लिया गया. प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन को 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है.

सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे. सेवा

तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय है. सेवा तीर्थ-3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय होंगे. सेवा तीर्थ में ओपन फ्लोर बनाने का मकसद औपचारिकताओं को कम करना, अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़ाना और आपसी पारदर्शिता की भावना को विकसित करना है. सेवा तीर्थ को एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों, उन्नत साइबर सुरक्षा नेटवर्क और एकीकृत सुरक्षा वास्तुकला से लैस किया गया है. यह इमारत भूकंप प्रतिरोधी है. कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय स्थित हैं. दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, संरचित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं हैं. आगंतुकों के लिए सुगम वातावरण सुनिश्चित होता है.

गुलामी की मानसिकता और नहीं चलेगी

सेवा तीर्थ के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतें ब्रिटिश शासन की हुकूमत की प्रतीक थीं. ये भवन ब्रिटेन के महाराज की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम था. हमें गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी था. दिल्ली की इमारतों में ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह भरे पड़े हैं. आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए, यहां उनके लिए कोई स्मारक नहीं था. 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता और नहीं चलेगी. हमारे इन फैसलों के पीछे हमारी सेवा भावना है. पीएम ने नए भवन को कर्म भूमि बताते हुए विजया एकादशी पर नया संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि पुरानी इमारत में म्युजियम बनेंगे. सेवा तीर्थ में जनता की उम्मीदें पूरी होंगी. यहां सत्ता के मिजाज को सेवा भाव में बदला जाएगा.

पीएम मोदी की मुख्य बातें

- राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला.
- परिश्रम की पराकाष्ठा कर्तव्य है.
- सेवा की भावना भारत की आत्मा है
- आज भारत रिफार्म एक्स. पर सवार है.
- सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है.
- जनता के विचार हमारी शक्ति है.
- पीएम दफ्तर का नया पता सेवा तीर्थ.
- हम जिम्मेदारी निभाने आए हैं.
- हमारा संकल्प इतिहास लिखेगा.
- जनता की आकांक्षा मार्गदर्शन है.
- पहले नायकों का सम्मान नहीं हुआ.
- उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाएगा.
- नाम बदलने के पीछे स्वतंत्र भारत की पहचान उजागर करना है.
- भवन परिसरों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं.
- आगंतुकों के लिए सुगम वातावरण.

जनगणना का वैश्विक महत्व : सीएम यादव

जनगणना 2027 के प्रथम चरण का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन

भोपाल, 13 फरवरी. जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शुभारंभ किया. इस अवसर पर जनगणना-2027 की प्रक्रिया पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया.

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सत्र में मुख्य सचिव अनुराग जैन, रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव गृह शिवशेखर शुक्ला उपस्थित थे. सम्मेलन में प्रदेश के सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्त तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हुए.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा है कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है. जनगणना के आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है. आज भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है. यह जनगणना केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व की भी है. जनगणना का कार्य केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे व्यापक और निर्णायक अभियान है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. उन्होंने कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से जनगणना कार्य को रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए जनगणना के सभी उद्देश्यों की समय सीमा में पूर्ति करने का आह्वान किया.

दो चरणों में होगी जनगणना

भारत की जनगणना विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है. भारत में जनांकिकीय व आर्थिक आंकड़ों का ग्राम एवं वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराने का एकमात्र स्रोत है. आगामी जनगणना 2027 पूर्व की जनगणनाओं की भांति इस बार भी 2 चरण में संपादित की जाएगी, जिसके लिए जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना 16 जून 2025 जारी की जा चुकी है. इसी क्रम में मध्यप्रदेश राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य 1 मई से 30 मई 2027 तक पूर्ण किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में जारी की जा चुकी हैं. द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी, 2027 में कराया जाएगा.

पुरी के इस्तीफे को लेकर संसद में हंगामा

- हंगामे के बीच लोकसभा-राज्यसभा 9 मार्च तक स्थगित
- बीजेपी बोली- राहुल सत्ता पाने को देश का बंटवारा चाहते थे

नई दिल्ली, 13 फरवरी. संसद में शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया. इसी के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक को नौ मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया. लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका.

सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए. बता दें कि दूसरा चरण 23 दिन के ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा. इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि वे सत्ता पाने के लिए देश के बंटवारे की प्लानिंग कर रहे थे. दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और टुकड़े-टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी जी के खिलाफ मेरे आरोप ये हैं, जिनके लिए मैंने लोकसभा स्पीकर से बहस करने की इजाजत मांगी है.

पुनीत बने थाईलैंड में भारत के नए राजदूत

नई दिल्ली, 13 फरवरी. पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी वर्तमान समय में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पुनीत अग्रवाल एक अनुभवी भारतीय डिप्लोमैट और इंडियन फॉरेन सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें थाईलैंड में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया. 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी अग्रवाल की पिछली भूमिकाओं में जिनेवा में राजदूत और डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और हांगकांग में कॉन्सुल जनरल शामिल हैं.

एक नजर में

25 लाख टन गेहूं के निर्यात को हरी झंडी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 लाख टन गेहूं के निर्यात के साथ-साथ 5 लाख टन गेहूं उत्पादों और चीनी के निर्यात की अनुमति दी. यह कदम पर्याप्त स्टाक की स्थिति को देखते हुए उठाया गया है. यह फैसला घरेलू बाजारों को स्थिर करने और किसानों को पर्याप्त लाभ दिलाने के लिए लिया गया है. खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वर्तमान उपलब्धता और कीमतों के आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है. अभी निजी संस्थाओं के पास 2025-26 के दौरान गेहूं का स्टाक लगभग 75 लाख टन है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 32 लाख टन अधिक है.

अमेरिका के विवि में गोलीबारी में दो की मौत

वाशिंगटन. अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय के परिसर में हुई गोलीबारी की एक घटना में दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. यह घटना गुरुवार शाम ह्यूजाइन सूट्स छात्र आवासीय परिसर में हुई. घटना के बाद विश्वविद्यालय ने परिसर में लॉकडाउन लागू कर दिया है. दक्षिण कैरोलिना कानून अनुपालन विभाग इस मामले की जांच कर रहा है.

पंचशील समझौता क्यों चाहते थे पीएम नेहरू

- सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान
- भारत हिमालयी रणनीति मंच का आयोजन

नई दिल्ली, 13 फरवरी. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को भारत-चीन संबंध को लेकर बयान दिया. वे देहरादून के लोक भवन में आयोजित भारत हिमालयी रणनीति मंच में स्पीच दे रहे थे.

उन्होंने बताया कि आखिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ 1954 का पंचशील समझौता क्यों चाहते थे, जिसमें भारत द्वारा तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देना शामिल था.

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेज चले गए और यह भारत को तय करना था कि सीमा कहां है. नेहरू शायद जानते थे कि पूर्व में मैकमोहन रेखा के रूप में हमारा कुछ दावा था और लद्दाख क्षेत्र में भी हमारा कुछ दावा था, लेकिन यहां नहीं. इसलिए शायद वे पंचशील समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहते थे. उन्होंने कहा, चीनी भी यही सोचते थे. जब चीनियों ने तिब्बत को एक तरह से मुक्त कराया तो वे ल्हासा में घुस गए. वे शिनजियांग में घुस गए. यह विशेष क्षेत्र दोनों छोरों पर बेहद खतरनाक था.

जनरल चौहान ने कहा, इसलिए इस क्षेत्र को किसी न किसी रूप में प्राथमिकता दी गई. वे शायद इस विशेष क्षेत्र में स्थिरता चाहते थे. स्वतंत्र भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक था. 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दी.

मेडागास्कर में चक्रवात गेजानी का कहर

नई दिल्ली, 13 फरवरी. हिंद महासागर स्थित मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी के तट से टकराने के बाद 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 से अधिक लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि तेज हवाओं और इमारतों के ढहने से अधिकांश मौतें पूर्वी बंदरगाह शहर टोमासिना में हुई. 15 लोग अब भी लापता हैं और 2,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. चक्रवात टोमासिना से टकराया, जहां हवाओं की रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक दर्ज की गई. राष्ट्रीय जोखिम एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार, कई मकान ढह गए.

रहमान की अगुवाई में बीएनपी की जीत

210 सीटों पर ऐतिहासिक जीत

बांग्लादेश संसदीय चुनाव

ढाका, 13 फरवरी (वार्ता) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने निर्वासन से लौटे तारिक रहमान की अगुवाई में संसदीय चुनावों में शानदार जीत हासिल की है. नवीनतम गणना के अनुसार, पार्टी ने चुनाव लड़ी गयी 299 सीटों में से लगभग 210 सीटों पर जीत दर्ज की है. देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी.

मुख्य प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया है. परिणाम घोषित होने के बाद जारी एक बयान में जमात-ए-इस्लामी ने कहा कि वह चुनाव परिणामों से जुड़ी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है. जमात ने दावा किया कि उसके 11-दलीय चुनावी गठबंधन के उम्मीदवार कई निर्वाचन क्षेत्रों में बेहद कम अंतर और संदिग्ध तरीके से हार गए. चुनाव में जीत के बाद बीएनपी ने शेख हसीना को भारत से वापस बांग्लादेश लाकर मुकदमा चलाने की मांग पर फिर से जोर दिया है. बीएनपी के सीनियर नेता सलाहुद्दीन अहमद ने शुक्रवार को कहा, 'हम हमेशा कानून के अनुसार उनकी वापसी की मांग करते रहे हैं.

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट | 10 पायदान ऊपर चढ़कर 75वें स्थान पर पहुंचा भारतीय पासपोर्ट

भारतीय पासपोर्ट ने ग्लोबल लेवल पर लगाई लंबी छलांग

नई दिल्ली, 13 फरवरी. दुनियाभर में अब भारतीय पासपोर्ट की ताकत और बढ़ गई है. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट ने ग्लोबल लेवल पर एक लंबी छलांग लगाई है.

भारत अब 10 पायदान ऊपर चढ़कर 75वें स्थान पर पहुंच गया है. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भारतीयों के लिए दुनिया की सैर करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. अब आपको कई देशों की यात्रा के लिए हफ्तों पहले वीजा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

पासपोर्ट की इस नई रैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा भारतीय यात्रियों को मिलने वाला है. अब आप बिना किसी झंझट के दुनिया के 56 देशों में बेफिक्र होकर घूम सकते हैं. इन देशों में या तो आपको वीजा की जरूरत नहीं होगी, या फिर वहां पहुंचते ही आपको वीजा-ऑन-अराइवल और ई-वीजा की सुविधा मिल जाएगी. चाहे आपको कैरेबियन द्वीप समूह के बीच पर सुस्ताने जाना हो या अफ्रीका और एशिया के खूबसूरत देशों की सैर करनी हो, अब आपका इंडियन पासपोर्ट आपके सफर को और भी आसान बना देगा.

आखिर कैसे तय होती है पासपोर्ट की मजबूती: दुनिया भर में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को पासपोर्ट की ताकत मापने का सबसे भरोसेमंद पैमाना माना जाता है. यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा का इस्तेमाल करके यह बताता है कि किस देश का नागरिक कितनी आसानी से अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर सकता है. रैंकिंग जितनी अच्छी होगी, उस देश के नागरिकों को दूसरे देशों में उतनी ही ज्यादा एंट्री की आजादी मिलेगी.

पहले नंबर पर है सिंगापुर

भले ही भारत ने जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन यात्रा की आजादी के मामले में कई देश अब भी वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर बने हुए हैं. इस लिस्ट में सिंगापुर एक बार फिर पहले नंबर पर है, जहां के नागरिक दुनिया के 192 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं. दूसरे पायदान पर जापान और दक्षिण कोरिया का कब्जा है, जिनके पासपोर्ट पर 187 देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है. तीसरे स्थान पर स्वीडन और यूएई ने अपनी जगह बनाई है, जहां के यात्री 186 देशों में बेधड़क दाखिल हो सकते हैं.

पीएम मोदी की नीतियां भारतीयों के लिए लाभकारी : रूवेन अजार

वॉशिंगटन, 13फरवरी. इजरायल और हमास के बीच ट्रंप के 20 सूत्रीय समझौते के तहत दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है. ट्रंप की अध्यक्षता में इस बोर्ड में कई देश शामिल हो चुके हैं.

इस बीच भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने बातचीत में बताया कि ट्रंप का 20 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौता गाजा में कितना असरदार है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो वहां कैसे हालात होंगे. इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व और प्रभाव को लेकर भी बातें की.

वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व और प्रभाव को लेकर इजरायली राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में जिन नीतियों को प्रमोट कर रहे हैं, वे भारतीय लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही हैं. सच तो यह है कि करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं. सच तो यह है कि यह देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है. सच तो यह है कि आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ है जो नए उद्योग बना रही है, इनोवेशन कर रही है, एकेडमिक रिसर्च कर रही है.